Regarding execution of Administrative work by Central Government through contractual workers

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : माननीय सभापति महोदय, आज मैं आपके माध्यम से देश की सरकार के सामने और कई प्रांतों की सरकारों के भी सामने समाज के उन सबसे ज्यादा मजबूर लोगों की आवाज़ उठाना चाहता हूँ, जिनको हम संविदाकर्मी के नाम से जानते हैं ।

अभी पिछले दिनों केरल की आशा बहुओं की आवाज़ उठी थी । इसी तरह के हालात पूरे देश के अन्दर है । अगर हम केवल उत्तर प्रदेश की बात करें, तो 4 लाख आशा बहुएं हैं, इनको रजिस्ट्रेशन के लिए दो हजार रुपए मिलते हैं और छ: सौ रुपए प्रति केस मिलते हैं । लगभग 40 हजार रोजगार सेवक हैं, जिनको केवल 8,850 रुपए मिलते हैं । शिक्षा मित्र लगभग 1 लाख 48 हजार हैं, जिनका मानदेय 10 हजार रुपए है । आंगनबाड़ी सहायिकाएं और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की संख्या लगभग साढ़े सात लाख है, इनको मानदेय के रूप में केवल 5 हजार रुपए और 2,700 रुपए मिलते हैं । इसी तरह से, लगभग 40 हजार अनुदेशक हैं, जिनका मानदेय केवल 8,700 रुपए है । पंचायत सहायक लगभग 40 हजार हैं, जिनका मानदेय केवल 5 हजार रुपए है । 3,76,796 रसोइए हैं, जिनका मानदेय केवल दो हजार रुपए है । ग्रामीण चौकीदारों की अलग समस्याएं हैं ।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से, जिसने रोजगार देने के लगातार वायदे किये, पाँचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था के भाषण चलते हैं, बीजेपी के लोग जो देश के अन्दर सम्पन्नता का डंका बजा रहे हैं, जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, जो डबल इंजन की बातें करते हैं, जो दुनिया में सबसे बेहतर इकोनॉमी की बातें करते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि अकेले उत्तर प्रदेश के अन्दर लगभग 18 लाख कर्मचारियों का यह हाल है । अगर इसी रेशियो में देखेंगे, तो पूरे देश में लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारियों की दुर्दशा है । इसके साथ ही, इस बात का आश्चर्य है कि इसमें कहीं भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के बनाये हुए संविधान के अनुसार, दलित भाइयों को जो रिज़र्वेशन मिलना चाहिए, पिछड़ों को जो रिज़र्वेशन मिलना चाहिए था, उसका कहीं कोई प्रावधान नहीं है । नित नये षडयंत्र हैं कि कैसे रिज़र्वेशन को खत्म करें । अगर सीधे रिज़र्वेशन को खत्म नहीं कर पा रहे हैं, तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से उसे खत्म कर रहे हैं । आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का इतना शोषण हो रहा है कि मनचाही एजेंसियाँ हायर हो रही हैं । अगर सरकार आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए 10 हजार रुपए देती है, तो उन कर्मचारियों तक तीन हजार रुपए से ज्यादा पेमेंट नहीं जाता है ।

इसलिए आपके माध्यम से मेरी मांग है कि तमाम संविदाकर्मियों को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा मिले, इन कर्मचारियों की भर्ती में आरक्षण का पालन किया जाए, इन कर्मचारियों की भर्ती के तहत उनको और उनके परिवार को दी जाने वाली सुविधाएं, जैसे ईपीएफ आदि तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए।

सभापति जी, आप यह बात सोचिए कि अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 1,500 से ज्यादा शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या की है । ? (व्यवधान) रक्षा मंत्री जी यहां बैठे हैं । ? (व्यवधान) रक्षा मंत्री जी, आप बताइए कि क्या आप इस बात से सहमत हैं? ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : डॉ. निशिकान्त दुबे जी ।

? (व्यवधान)